resources. There is variation in the price of the crude oil, and we have to go ahead aggressively to find more oil.

MR. CHAIRMAN: Now, we will take up the next question. Question No. 325.

सोयाबीन का समर्थन मूल्य

*325. **राधाकिशन मालवीय:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश, शासन द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि लागत और मूल्य आयोग ध्यान देता है; और

(ख) क्या आगामी वर्षों में सोयाबीन का समर्थन मूल्य राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार घोषित किया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) जी, हां।

(ख) कृषि लागत और मूल्य आयोग सोयाबीन की काली और पीली किस्मों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश करते समय मध्य प्रदेश सहित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों और अन्य महत्वपूर्ण घटकों जैसे, उत्पादन लागत, आदान मूल्यों में परिवर्तन, आदान/पैदावार मूल्य समतुल्यता, बाजार मूल्यों की प्रवृत्ति, मांग तथा आपूर्ति की स्थिति, अन्त: फसल मूल्य समतुल्यता, औद्योगिक लागत ढांचे पर प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य की स्थिति, व्यापार की शर्तों आदि को ध्यान में रखता है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करते समय, कृषि लागत और मूल्य आयोग तथा राज्यों व केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों को ध्यान में रखा जाता है।

श्री राधाकिशन मालवीय: सभापति महोदय, मध्य प्रदेश सोयाबीन राज्य के नाम से जाना जाता है। देश का 80 प्रतिशत सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है। सोयाबीन इस प्रदेश की खरीफ फसलों में एक मुख्य फसल है। राज्य सरकार द्वारा काले और पीले सोयाबीन का जो समर्थन मूल्य प्रस्तावित किया जाता है, कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा उस पर गंभीरता से विचार न करके सिफारिश को नज़रअंदाज किया जाता है। वर्ष 1998 में राज्य सरकार ने काले सोयाबीन का मूल्य 950 रुपए प्रति क्विंटल और पीले सोयाबीन का मूल्य 1,050 रुपए प्रति क्विंटल प्रस्तावित किया था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भारत सरकार के कृषि लागत और मूल्य आयोग ने सोयाबीन का जो मूल्य निर्धारित किया था वह 917 रुपए प्रति क्विंटल था, सरकार ने कम मूल्य क्यों निर्धारित किया?

श्री सोमपाल: सभापति महोदय, माननीय मालवीय जी का यह कथन सत्य है कि मध्य प्रदेश सरकार ने पीले सोयाबीन का दाम 1,050 रुपए प्रति क्विंटल और काले सोयाबीन का दाम 950 रुपए प्रति क्विंटल मांगा था, प्रस्तावित किया था। जैसा मैंने कहा कि विभिन्न कारकों की ध्यान में रखते हुए और विभिन्न मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, उसकी मांग और आपूर्ति और उसके जो सामान्य प्रभाव हैं ....(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Now, Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Schemes for Unemployed Youth

*326. SHRI W. ANGOU SINGH: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) the scheme of his Ministry to help unemployed youth under P.M's Self Employment Scheme;

(b) the number of beneficiaries of this scheme allotted to each State; and

(c) whether the beneficiaries of this scheme are appointed by Government or oil companies?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI K. RAMAMURTHY): (a) to (c) Recently a Scheme known as "Prime Minister's Self Employment Scheme of Oil Companies" has been launched. Under this Scheme, Oil Industry has made a plan for setting up one SKO (Kerosene) retail dealership in every Development Block of the country. Salient features of the Schheme are described below.

(1) There will be one retails kerosene dealership at each Block Headquarters in the country.

(2) The dealers will be selected and appointed by the concerned oil companies.

(3) Reservation has been provided as follows:

Scheduled Castes/ Sceduled Tribes	-	25%
Pysically Handicapped Persons	-	6%